Haryana Vidhan Sabha

14/16/173

To complete the construction work of power plant

26/07/2023 26/07/2023

*14/16/173 श्री कुलदीप वत्स(बादली)

ऊर्जा मंत्री

will the Power Minister be pleased to state:-

गुरुग्राम और फरीदाबाद के कूड़े के निदान एवं कूड़े से बिजली बनाने के लिए गुरुग्राम के बधवारी में पावर प्लाट लगाने हेतु राज्य सरकार ने इको ग्रीन एनर्जी कंपनी जोकि चाइना की है. के साथ अगस्त 2017 में अनुबंध किया गया था। जिसके अंतर्गत कम्पनी को सात साल की अवधि में प्लांट को तैयार करना था | सात वर्ष तक कूड़ा उठाने और उसकी प्रोसेसिंग के लिए राज्य सरकार इको ग्रीन कंपनी को 1000 रुपये प्रति मीट्रिक टन भुगतान बहन कर रही है. इको ग्रीन कंपनी के द्वारा कूड़ा तो उठाया गया परन्तु उसकी प्रोसेसिंग की कोई भी प्रक्रिया नहीं की। जिसके उपरान्त नगर निगम गुरुग्राम उस कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया करके 315 रूपये प्रति मीट्रिक टन भुगतान कर रही है। क्या यह 315 रूपये प्रति मीट्रिक टन भुगतान राज्य सरकार ने इको ग्रीन कंपनी के भुगतान से काटे है या नहीं काटे | अगर नहीं काटे तो क्या राज्य सरकार चाइना की कंपनी से मिली भगत करके अलग से फायदा पहुंचा रही है। अनुबंध के अंतर्गत ही इको ग्रीन कंपनी को घर-घर से कूड़ा उठाना था जोकि कंपनी घर-घर से कूड़ा ना उठाकर कूड़ा घर या उसान से कूड़ा उठा रही है, इस बात में सरकार इनको विशेष छूट फिस मंशा से दे रही है। पिछले वर्ष भी दिसम्बर 2022 में माननीय मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया था और उसको पूर्ण करने की समय सीमा दिसम्बर 2023 तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही निर्धारित कर दी थी। मैं सदन के माध्यम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता है कि 2017 से अब तक पावर प्लांट का कितना कार्य हो चूका

है और कितना काम बचा हुआ है। क्या शेष काम बच्चे शेष समय 5 महीने में पूरा हो पाएगा | हरियाणा सरकार इस काम को निर्धारित समय पर पूरा करवाने के लिए कितनी गंभीर है, उसके बाद भी अगर यह प्लांट निर्धारित समय पर भी तैयार नहीं हुआ तो क्या हरियाणा सरकार ने इस कम्पनी पर जुर्माने का कोई प्रावधान कर रखा है। में सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि अब तक हरियाणा सरकार ने इको ग्रीन कम्पनी को कितना भुगतान किया है ? साथ ही यह भी पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने 2017 से अब तक किन-किन कंपनियों को पावर प्लाट से संबंधित कितना-कितना भुगतान किया है। मुझे लगता है कि सरकारी अधिकारियों व ठेकेदारों की मिली-भ -भगत से इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कृपया

कर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पर विस्तार से बताए ।